न्यायाधीश *बी.एस वालिया* के समक्ष।

साहून - अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती जुबैदा और अन्य—प्रतिवादी

2015 का एफएओ संख्या 5926

सितम्बर 17, 2018

मोटर यान अधिनियम***, 1988-*** धारा ***149(2)(***ए***)(ii) -*** चालक को काम पर रखने पर बीमित व्यक्ति का दायित्व **-** बीमा कंपनी को दिए गए वसूली अधिकारों को चुनौती दी गई **-** आयोजित**,** मालिक को योग्य और सक्षम चालक को नियुक्त करते समय उचित सावधानी बरतने की उम्मीद नहीं है **-** चालक को काम पर रखने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की उम्मीद नहीं है **-** बीमा कंपनियों द्वारा मालिक की ओर से उचित देखभाल करने में विफलता स्थापित करने के लिए **-** लिखित बयान में अस्पष्ट दलील देना पर्याप्त नहीं है **-** अपील खारिज कर दी गई।

(2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूत, 2007 (2) आरसीआर (सिविल) 345 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रासंगिक समय पर चालक का नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस बीमाधारक या तृतीय पक्षों के विरुद्ध बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं था और बीमित व्यक्ति के प्रति इसके दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा था या जो प्रासंगिक समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था और यह हमेशा अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बीमाकर्ता के लिए खुला था कि वह बचाव करे कि दुर्घटना में शामिल वाहन विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं था और इस तरह के बचाव पर जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होगी, लेकिन यह साबित होने के बाद भी कि ड्राइवर के पास मौजूद लाइसेंस नकली लाइसेंस था, सवाल यह होगा कि क्या बीमित व्यक्ति पर कोई दायित्व था जब वह ड्राइवर को काम पर रखता है। इसके संबंध में, यह माना गया कि जहां तक वाहन के मालिक का संबंध था, जब उसने एक ड्राइवर को काम पर रखा था, तो उसे यह जांचना था कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तत्पश्चात्, उसे चालक की सक्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना पड़ा और यदि वह इस संबंध में भी संतुष्ट हो जाता है तो यह कहा जा सकता है कि मालिक ने वाहन चलाने के लिए योग्य और सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने में उचित सावधानी बरती थी और उससे चालक की सेवाएं लेने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की सीमा तक जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

(पैरा 11)

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूत, 2007 (2) आरसीआर (सिविल) 345 में यह निर्णय दिया कि संगत समय पर चालक का नकली अथवा अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस बीमाधारक अथवा तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं था और बीमित व्यक्ति के प्रति इसके दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा था या जो प्रासंगिक समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था और यह हमेशा अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बीमाकर्ता के लिए खुला था कि वह बचाव करे कि दुर्घटना में शामिल वाहन विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं था और इस तरह के बचाव पर जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होगी, लेकिन यह साबित होने के बाद भी कि ड्राइवर के पास मौजूद लाइसेंस नकली लाइसेंस था, सवाल यह होगा कि क्या बीमित व्यक्ति पर कोई दायित्व था जब वह ड्राइवर को काम पर रखता है। इसके संबंध में, यह माना गया कि जहां तक वाहन के मालिक का संबंध था, जब उसने एक ड्राइवर को काम पर रखा था, तो उसे यह जांचना था कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तत्पश्चात्, उसे चालक की सक्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना पड़ा और यदि वह इस संबंध में भी संतुष्ट हो जाता है तो यह कहा जा सकता है कि मालिक ने वाहन चलाने के लिए योग्य और सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने में उचित सावधानी बरती थी और उससे चालक की सेवाएं लेने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की सीमा तक जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

(पैरा 16)

अपीलकर्ता के लिए अमन बंसल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और 5 के लिए कोई नहीं।

सचिन ओहरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 4-बीमा कंपनी के लिए।

बीएस वालिया**,** जे **(**मौखिक**)**

(1) यह आदेश 2015 के एफएओ संख्या 5926 और 5928 का निर्णय करेगा क्योंकि वे दिनांक 13.11.2014 के सामान्य अधिनिर्णय से उत्पन्न होते हैं, इसके अलावा दोनों मामलों में समान प्रश्न शामिल हैं। हालांकि, 2015 के एफएओ संख्या 5926 से तथ्य लिए गए हैं।

(2) मालिक साहून द्वारा प्रतिवादी नंबर 4-बीमा कंपनी को दिए गए वसूली अधिकारों के खिलाफ अपील दायर की गई है, जो 18.08.2012 को सुभान खान के साथ मोटर वाहन दुर्घटना में मारे गए एक तालीम की विधवा

और दो नाबालिग बच्चों को दिए गए 7,15,000 रुपये के मुआवजे के बराबर है।

(3) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेवात (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल, मेवात' के रूप में संदर्भित) ने अपने फैसले दिनांक 13.11.2014 के तहत तालीम की विधवा और दो नाबालिग बच्चों को मुआवजा देते हुए, बीमा कंपनी को इस आधार पर वसूली अधिकार प्रदान किया कि बीमा कंपनी के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर उल्लंघन करने वाले वाहन यानी फकरू के चालक का लाइसेंस फर्जी पाया गया था।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दो दावा याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थीं, यानी एक तालीम की मृत्यु के कारण, जिसमें से तत्काल अपील उत्पन्न होती है और जिसके संबंध में 13.11.2014 को पुरस्कार पारित किया गया था, जबकि दूसरी दावा याचिका सुभान खान की मृत्यु के कारण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी, नूह (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल, नूह' के रूप में संदर्भित)। विद्वान न्यायाधिकरण, नूंह ने अपने फैसले दिनांक 31.10.2013 के माध्यम से पाया कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी फकरू, चालक के पास दुर्घटना की तारीख को एक वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था और बीमा कंपनी के वकील यह साबित करने में विफल रहे थे कि मालिक और ड्राइवर ने बीमा पॉलिसी के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया था।

(5) विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक बार ट्रिब्यूनल, नूंह ने अपने फैसले दिनांक 31.10.2013 में उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक (यानी फकरू) के लाइसेंस को वास्तविक पाया था, तो ट्रिब्यूनल, मेवात द्वारा इसके संबंध में एक अलग निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता था। नतीजतन, अपीलकर्ता से प्रतिवादी-बीमा कंपनी को वसूली के अधिकार देने वाले विद्वान ट्रिब्यूनल, मेवात के निष्कर्ष कानूनी रूप से अस्थिर थे और इसे अलग रखा जाना था।

(6) प्रतिवाद, प्रतिवादी नंबर 4-इंश्योरेंस कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रिब्यूनल नूंह के समक्ष दावा याचिका में, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के पास लाइसेंस के नकली होने का सबूत उपलब्ध नहीं था और यह केवल ट्रिब्यूनल, मेवात के समक्ष तालीम से संबंधित मामले में किए गए प्रयासों के आधार पर था कि यह आरटीओ के कार्यालय से पाया गया था, मथुरा ने मथुरा में कहा है कि फकरू को जारी किए गए लाइसेंस को कभी भी जारी नहीं किया गया था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया गया था, हालांकि आरटीओ, गुड़गांव द्वारा इसका नवीकरण किया गया था।

(7) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने राम चंद्र सिंह बनाम राजाराम और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या ***11*** पर भरोसा किया है कि यह केवल तभी है जब मालिक को चालक के लाइसेंस के नकली होने के बारे में पता था और फिर भी चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी, कि बीमाकर्ता दायित्व से मुक्त हो जाएगा और केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, बीमाकर्ता को दायित्व से मुक्त नहीं करना।

निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> "11. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि मालिक इस तथ्य से अवगत था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी 4 चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी, तो बीमाकर्ता दोषमुक्त हो जाएगा। हालांकि, केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली है, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करेगा। निस्संदेह, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया था, लेकिन यह रियायत अपने आप में बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

(8) विद्वान वकील ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ संख्या ***20*** पर भरोसा किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चालक को काम पर रखते समय यदि चालक एक ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करता है जो उसके चेहरे पर वास्तविक दिखता है तो मालिक से यह पता लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या लाइसेंस वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं। मालिक तब चालक का परीक्षण करेगा और यदि वह पाता है कि चालक वाहन चलाने के लिए सक्षम है, तो वह चालक को काम पर रखेगा। पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "20. जब कोई मालिक ड्राइवर को काम पर रख रहा होता है तो उसे यह जांचना होगा कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। यदि चालक कोई ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करता है जो दिखने में वास्तविक लगता है तो मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह यह पता लगाए कि लाइसेंस वास्तव में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है या नहीं। इसके बाद मालिक ड्राइवर की परीक्षा लेगा। यदि वह पाता है कि चालक वाहन चलाने के लिए सक्षम है, तो वह चालक को काम पर रखेगा। हमें यह अजीब लगता है कि बीमा कंपनियां मालिकों से आरटीओ के साथ पूछताछ करने की उम्मीद करती हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं, चाहे उन्हें दिखाया गया ड्राइविंग लाइसेंस वैध है या नहीं। इस प्रकार, जहां मालिक ने खुद को संतुष्ट कर लिया है कि चालक के पास लाइसेंस है और वह सक्षम रूप से गाड़ी चला रहा है, तो धारा 149 (2) (ए) (ii) का कोई उल्लंघन नहीं होगा। तब बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि अंततः यह पता चलता है कि लाइसेंस नकली था, तो बीमा कंपनी तब तक उत्तरदायी बनी रहेगी जब तक कि वे यह साबित नहीं करते कि मालिक / बीमित व्यक्ति को पता था या उसने देखा था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी उस व्यक्ति को ड्राइव करने की अनुमति दी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामले में भी बीमा कंपनी निर्दोष तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी रहेगी; लेकिन यह बीमित व्यक्ति से

उबरने में सक्षम हो सकता है। यह वह कानून है जो स्कैंडिया, सोहन लाल पासी और कमला के मामले में निर्धारित किया गया था। हम उसमें व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

(9) विद्वान वकील का तर्क है कि परिस्थितियों में, एक बार यह स्वीकार की गई स्थिति है कि ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वह नकली था, आरटीओ कार्यालय, गुड़गांव द्वारा नवीनीकृत किया गया था, तो उस स्थिति में बीमाकर्ता दावेदार को मुआवजे का भुगतान करने और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक के खिलाफ वसूली अधिकारों का दावा करने के दायित्व से खुद को मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि बीमा कंपनी इस रुख को नहीं ले सकती है कि मालिक द्वारा पॉलिसी की शर्तें। इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बचाव करने की हकदार है कि उल्लंघन करने वाला वाहन अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हालांकि, बीमा कंपनी पर जिम्मेदारी तभी बदलेगी जब उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक अपनी जानकारी के भीतर बुनियादी तथ्यों को साबित करेगा कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और प्रासंगिक समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और लिखित बयान में केवल एक अस्पष्ट दलील दी गई थी कि उल्लंघन करने वाले वाहन को वैध ड्राइविंग वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था चालक के नाम के साथ-साथ उसके अन्य विवरणों के प्रकटीकरण के अभाव में लाइसेंस पर्याप्त नहीं होगा।

(10) विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश करने के अभाव में कि समर्थन में पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति एक ऐसे व्यक्ति की थी, जो वास्तव में प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था, वाहन के मालिक को दायित्व से निकाला नहीं जा सकता है।

(11) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार किया है। यह दुर्घटना 18082012 को हुई थी। अपीलकर्ता यानी प्रतिवादी नंबर 1 ने ट्रिब्यूनल, मेवात के समक्ष लिखित बयान के पैराग्राफ नंबर 23 में तर्क दिया कि उसके पास वाहन के पूरे दस्तावेज थे और फकरू (प्रतिवादी नंबर 2) यानी चालक के पास कथित उल्लंघन करने वाले वाहन की दुर्घटना के समय वैध लाइसेंस था।

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत के आदेश में कहा था कि प्रासंगिक समय पर चालक का नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं था और बीमित व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति

लापरवाही का दोषी था और वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक या जिसे प्रासंगिक समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया था और यह हमेशा अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बीमाकर्ता के लिए खुला था कि वह बचाव करे कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक को विधिवत लाइसेंस नहीं दिया गया था और इस तरह के बचाव पर लिया जा रहा था, जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होगी, लेकिन यह साबित होने के बाद भी कि ड्राइवर के पास लाइसेंस एक नकली लाइसेंस था, सवाल यह होगा कि क्या बीमाधारक पर कोई दायित्व था जब वह ड्राइवर को काम पर रखता है। इसके संबंध में, यह माना गया कि जहां तक वाहन के मालिक का संबंध था, जब उसने एक ड्राइवर को काम पर रखा था, तो उसे यह जांचना था कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तत्पश्चात्, उसे चालक की सक्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना पड़ा और यदि वह इस संबंध में भी संतुष्ट हो जाता है तो यह कहा जा सकता है कि मालिक ने वाहन चलाने के लिए योग्य और सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने में उचित सावधानी बरती थी और उससे चालक की सेवाएं लेने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की सीमा तक जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

(13) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मामले में पारित निर्णय के पैराग्राफ संख्या ***7*** से ***10*** [1] को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> "**7**. स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा) पर बाद में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूत**, 2007 (2)** आरसीआर **(**सिविल**) 345: 2007 (1)** हालिया शीर्ष निर्णय **(**राज**) 956: (2007) 3** एससीसी **700** में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह समझाया गया था कि:
>
> "केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता बीमाधारक या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। बीमित व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा था या जो प्रासंगिक समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था।
>
> 8. मुआवजे के दावे में, यह निश्चित रूप से धारा 149 (2) (ए) (ii)

[1] 2014 (1) एससीसी (एल एंड एस) 750

के तहत बीमाकर्ता के लिए यह बचाव करने के लिए खुला है कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक को विधिवत लाइसेंस नहीं दिया गया था। एक बार ऐसा बचाव करने के बाद, जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होती है। लेकिन यह साबित हो जाने के बाद भी कि ड्राइवर के पास जो लाइसेंस था वह फर्जी था, क्या बीमाकर्ता पर देयता है, यह विवादास्पद प्रश्न है। जहां तक वाहन के मालिक का संबंध है, जब वह किसी ड्राइवर को काम पर रखता है, तो उसे यह जांचना होता है कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। इसके बाद उसे ड्राइवर की क्षमता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। यदि उस संबंध में भी संतुष्ट हैं, तो यह कहा जा सकता है कि मालिक ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने में उचित सावधानी बरती है जो वाहन चलाने के लिए योग्य और सक्षम है। मालिक से इससे आगे जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ड्राइवर की सेवाएं लेने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की वास्तविकता को सत्यापित करने की सीमा तक। हालांकि, स्थिति अलग होगी यदि वाहन के बीमा के समय या उसके बाद बीमा कंपनी वाहन के मालिक को लाइसेंस प्राधिकारी से विधिवत सत्यापित लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है या यदि वाहन के मालिक का ध्यान अन्यथा इस आरोप की ओर आकर्षित किया जाता है कि उसके द्वारा नियोजित चालक को जारी किया गया लाइसेंस नकली है और फिर भी मालिक उचित कार्रवाई नहीं करता है लाइसेंस की प्रामाणिकता के संबंध में मामले के लाइसेंस की जांच के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त होने वाले लाइसेंस की प्रामाणिकता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा) में यही समझाया गया है। यदि मालिक के साथ ऐसी जानकारी के बावजूद कि उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नकली है, बीमाधारक द्वारा उचित सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बीमाधारक गलती पर होगा और ऐसी परिस्थितियों में, बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है।

9. तथ्यों के आधार पर, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता नियोक्ता ने 1994 में तीसरे प्रतिवादी निर्मल सिंह को ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया था। रोजगार की प्रक्रिया में, उसे ड्राइविंग टेस्ट दिया गया था और उसे प्रशिक्षण भी दिया गया था। यह दुर्घटना पीआरटीसी में ड्राइवर के रूप में उनकी सेवा के छह साल बाद ही हुई। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि बीमित व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने में गलती की है जिसका लाइसेंस बीमा कंपनी द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष नकली साबित हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, ट्रिब्यूनल के समक्ष लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साक्ष्य को स्कैन करने पर, यह भी पूरी तरह से नहीं

माना जा सकता है कि ड्राइवर को लाइसेंस उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया था और लाइसेंस नकली था। हालांकि अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया था कि मुआवजा अधिक है, लेकिन कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है और हमारे अनुसार उचित रूप से, उस स्थिति को कैनवास करने के लिए।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी जाती है। चौथा प्रतिवादी - बीमा कंपनी अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए, दावेदारों को पहले से भुगतान किए गए मुआवजे की कोई वसूली नहीं हो सकती है।

(14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में स्वर्ण सिंह और अन्य[2] के मामले में पैरा सं 110 के आधार पर यह तर्क दिया है कि बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा पॉलिसी शर्त का उल्लंघन किया जाना साबित किया जाना है और यह कि केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए चालक की अयोग्यता, बीमाधारक या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है और इससे बचने के लिए बीमित व्यक्ति के प्रति इसकी देयता, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा या जो प्रासंगिक समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था। पैराग्राफ संख्या 110 (iii), (iv) और (vii) का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"110. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार है: -

(3) पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन जैसे ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि धारा 149 की उप-धारा (2) (ए) (ii) में निहित है, बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा प्रतिबद्ध साबित होना चाहिए। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता, बीमाधारक या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमित व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा था या जो प्रासंगिक

[2] 2004 (3) एससीसी 297

समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था।

(4) बीमा कंपनियों, हालांकि, अपनी देयता से बचने के उद्देश्य से, न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव (ओं) को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से "उल्लंघन" भी स्थापित करना चाहिए; सबूत का बोझ उन पर होगा।

(vii) प्रत्येक मामले में यह प्रश्न कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए समुचित सावधानी बरती है कि चालक द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस (जाली लाइसेंस या अन्यथा) कानून की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है अथवा नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक मामले में करना होगा।

(15) इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 4-इंश्योरेंस कंपनी के विद्वान वकील ने सिंह राम बनाम निर्मला और अन्य[3] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया कि मालिक के साक्ष्य में गवाही नहीं देने और गवाह के कटघरे से दूर रहने के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि मालिक ने स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा) में प्रस्ताव (vii) के संबंध में उचित देखभाल की थी।

(16) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और मेरा विचार है कि पप्पू और अन्य बनाम विनोद कुमार लांबा और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर मामला अब एकीकृत नहीं है । उपरोक्त निर्णय के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीमा कंपनी अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बचाव करने की हकदार है कि उल्लंघन करने वाला वाहन अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हालांकि, बीमा कंपनी पर जिम्मेदारी तभी बदलेगी जब उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक अपनी जानकारी के भीतर बुनियादी तथ्यों को साबित करेगा और साबित करेगा कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और प्रासंगिक समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और केवल लिखित बयान में एक अस्पष्ट दलील उठाई गई थी कि उल्लंघन करने वाला वाहन वैध ड्राइविंग वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था चालक के नाम के साथ-साथ उसके अन्य विवरणों के प्रकटीकरण के अभाव में लाइसेंस पर्याप्त नहीं होगा।

(17) उपर्युक्त निर्णय में कहा गया है कि मालिक के गवाह-बॉक्स में प्रवेश करने या उपरोक्त याचिका के समर्थन में किसी गवाह की जांच करने की अनुपस्थिति में और बीमा कंपनी ने याचिका का खंडन किया है और यह भी दावा किया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था और न ही ऐसे चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई सबूत पेश किया था, जिसमें कोई विशिष्ट स्टैंड नहीं था। दलीलों या साक्ष्य में कि चालक

[3] 2018 (3) एससीसी 800

वास्तव में प्रासंगिक समय पर प्रश्न में वाहन चलाने के लिए अधिकृत था, बोनस बीमा कंपनी पर स्थानांतरित नहीं होगा जिसके लिए उसे इस तरह के सबूतों का खंडन करने और अपने बचाव को साबित करने के लिए अन्य सबूत पेश करने की आवश्यकता होगी और यह केवल बुनियादी तथ्यों की वकालत करने और आपत्तिजनक वाहन के मालिक द्वारा स्थापित करने के बाद ही है कि यह एक वैध अधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था ड्राइविंग लाइसेंस कि जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर स्थानांतरित हो जाएगी।

(18) तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लिखित बयान में चालक के नाम का खुलासा किए बिना या इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना कि समर्थन में पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति एक ऐसे व्यक्ति की थी जो वास्तव में प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था, वाहन के मालिक को दायित्व से निकाला नहीं जा सकता है। पैराग्राफ संख्या 11 जो इस मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> "11. प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य कि उल्लंघन करने वाले वाहन का प्रतिवादी नंबर 2 बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था, बीमा कंपनी को उत्तरदायी बनाएगा? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 (2) (ए) (ii) के तहत बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध बचावों पर ध्यान दिया है। बीमा कंपनी यह बचाव करने की हकदार है कि उल्लंघन करने वाला वाहन एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा दलील देने और अपने ज्ञान के भीतर बुनियादी तथ्यों को साबित करने के बाद ही बीमा कंपनी पर जिम्मेदारी बदल जाएगी कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और प्रासंगिक समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 के मालिक ने लिखित बयान में केवल एक अस्पष्ट दलील दी कि उल्लंघन करने वाला वाहन DIL-5955 वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने ड्राइवर के नाम और उसके अन्य विवरणों का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 ने इस याचिका के समर्थन में गवाह के कठघरे में प्रवेश नहीं किया और न ही किसी गवाह से पूछताछ की। प्रतिवादी नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी ने लिखित बयान में उस दलील का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और यह भी कहा है कि उल्लंघन करने वाला वाहन अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उल्लंघन करने वाले वाहन के प्रतिवादी नंबर 1 मालिक ने जोगिंदर सिंह के ड्राइविंग

लाइसेंस को छोड़कर कोई सबूत पेश नहीं किया, बिना किसी विशेष स्टैंड के दलीलों में या सबूतों में कोई विशिष्ट स्टैंड लिए बिना कि वही जोगिंदर सिंह वास्तव में प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था। इसके बाद ही प्रतिवादी नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी को इस तरह के सबूतों का खंडन करने और अपने बचाव को साबित करने के लिए अन्य सबूत पेश करने की आवश्यकता होगी। केवल उल्लंघन करने वाले ट्रक के संबंध में एक वैध बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना प्रतिवादी नंबर 1 के लिए बीमा कंपनी को अपने वाहन के चालक द्वारा तेज और लापरवाही से ड्राइविंग से उत्पन्न अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बीमा कंपनी को वैध बीमा पॉलिसी के आधार पर देयता के साथ तभी बांधा जा सकता है जब उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा बुनियादी तथ्यों की दलील दी जाती है और स्थापित किया जाता है - कि वाहन न केवल विधिवत बीमा किया गया था, बल्कि यह भी कि यह एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। लिखित बयान में ड्राइवर के नाम का खुलासा किए बिना या इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना कि समर्थन में पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति एक ऐसे व्यक्ति की थी, जो वास्तव में, प्रासंगिक समय पर आपत्तिजनक वाहन चलाने के लिए अधिकृत था, वाहन के मालिक को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने खुद को उसकी देयता से निकाला है। बीमा कंपनी तभी उत्तरदायी बनेगी जब इस तरह के मूलभूत तथ्यों की दलील दी जाएगी और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा साबित किया जाएगा।

(19)वर्तमान मामले में, लिखित बयान के पैराग्राफ संख्या 23 में, अपीलकर्ता ने यह रुख अपनाया कि उसके पास उल्लंघन करने वाले वाहन के पूरे दस्तावेज थे और प्रतिवादी नंबर 2 यानी उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास कथित उल्लंघन करने वाले वाहन की झूठी भागीदारी के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और बीमा कंपनी के साथ पूरी तरह से बीमा किया गया था, इसलिए, बीमा कंपनी याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। हालांकि, न तो मालिक द्वारा लिखित बयान में यह उल्लेख किया गया था कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और न ही अपीलकर्ता मालिक ने यह साबित करने के लिए गवाह के कटघरे में कदम रखा कि उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत था और उसके पास लिखित बयान में अस्पष्ट दलील देने के अलावा प्रासंगिक समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था कि आपत्तिजनक वाहन प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उपरोक्त याचिका के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा किसी गवाह की जांच नहीं की गई थी, जबकि बीमा कंपनी के विद्वान वकील के अनुसार, बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उल्लंघन करने वाला वाहन वैध

ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था जैसा कि अवार्ड के पैराग्राफ नंबर 6 से स्पष्ट है। दलील में या उसके संबंध में साक्ष्य में कोई विशिष्ट रुख नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 यानी फकरू वास्तव में प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था और न ही लिखित बयान में कुछ भी कहा गया है और न ही अपीलकर्ता के संबंध में कोई सबूत पेश किया गया था जिसने नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस का अवलोकन किया था और वाहन चलाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2-फकरू यानी चालक की क्षमता की जांच करने के बाद, उसे वाहन चलाने की अनुमति दी।

(20)इन परिस्थितियों में, राम चंद्र सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस का अवलोकन किया था और वाहन चलाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की क्षमता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद, उसे वाहन चलाने की अनुमति दी थी और आगे कहा कि उसने मूल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखा था। केवल तथ्य यह है कि बीमा कंपनी के नेतृत्व में किसी भी सबूत के अभाव में संबंधित अधिनिर्णय में विद्वान ट्रिब्यूनल, नूंह ने प्रतिवादी नंबर 2- फकरू के ड्राइविंग लाइसेंस को वैध माना, तत्काल मामले में अपीलकर्ता, जो वाहन के मालिक के रूप में भी पक्षकार था, यह दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि बीमा कंपनी द्वारा विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा याचिका में नेतृत्व किए गए साक्ष्य, मेवात की उपेक्षा की जाए या उसे दरकिनार कर दिया जाए और प्रतिवादी संख्या 2-फकरू के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में विद्वान अधिकरण, नूंह के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाए।

(21)इस मामले में, बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से सबूत पेश किए कि आरटीओ, मथुरा द्वारा प्रतिवादी नंबर 2-फकरू के पक्ष में जारी ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी साबित हुआ था। अपीलकर्ता ने न तो लिखित बयान में दावा किया है और न ही कोई सबूत दिया है कि उसने मूल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखा था, बल्कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण किया था और आगे कहा कि उसने वाहन चलाने की अपनी क्षमता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद प्रतिवादी नंबर 2-फकरू को नियुक्त किया था।

(22)इन परिस्थितियों में, बीमा कंपनी के पक्ष में वसूली अधिकार प्रदान करने वाले विद्वान अधिकरण, मेवात द्वारा पारित अधिनिर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और न ही विद्वान अधिकरण, नूंह द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को चुनौती देने के अभाव में अपीलकर्ता को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि विद्वान अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष, नूंह ने अपने पुरस्कार में, तत्काल मामले में पालन किया।

(23)ऊपर उल्लिखित स्थिति के आलोक में, अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

सुमति जुंड

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा